भारतीयों में बढ़ा घर खरीदने का भरोसा

31 प्रतिशत लोगों ने पांच साल में घर खरीदना बताया सबसे बड़ा लक्ष्य

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त भारतीयों की वित्तीय सोच में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. रोजमर्रा की जरूरतों और गैर-जरूरी खर्चों के बजाय अब लोग लंबे समय की आर्थिक सुरक्षा, संपत्ति बनाने और भविष्य के बड़े लक्ष्यों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं.

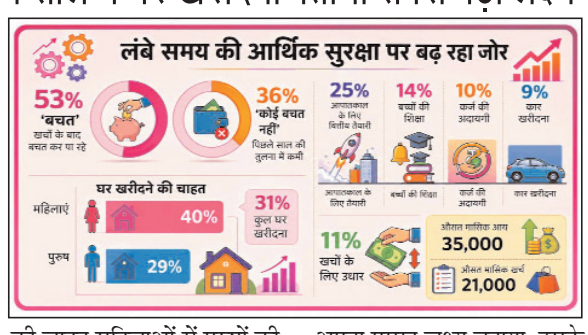

होम क्रेडिट इंडिया की 'द ग्रेट इंडियन वॉलेट 2026' रिपोर्ट के अनुसार, निम्न मध्यम वर्ग के 31 फीसदी लोगों ने अगले पांच वर्षों में अपना घर खरीदना सबसे बड़ा वित्तीय लक्ष्य बताया है. पिछले साल की तुलना में इस आंकड़े में आठ प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है. खास बात यह है कि घर खरीदने की चाहत महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कहीं अधिक है. सर्वे में 40 फीसदी महिलाओं ने अगले पांच वर्षों में घर खरीदने को अपनी प्राथमिकता बताया, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 29 फीसदी रहा. घर खरीदने के बाद 25 फीसदी लोगों ने कारोबार शुरू करने या मौजूदा कारोबार का विस्तार करने को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया. इसके अलावा 14 फीसदी लोग बच्चों की शिक्षा, 10 फीसदी कर्ज चुकाने और नौ फीसदी कार खरीदने को अगले पांच वर्षों का लक्ष्य मानते हैं. दोपहिया वाहन और विदेश यात्रा जैसे अपेक्षाकृत गैर-जरूरी लक्ष्यों की तुलना में संपत्ति और वित्तीय स्थिरता को अधिक महत्व मिलना इस बदलाव को दर्शाता है. शामिल लोगों की औसत मासिक आय करीब 35 हजार रुपये रही, जबकि जरूरी खर्च औसतन 21 हजार रुपये रहा. करीब 53 फीसदी लोग अपने जरूरी खर्च निकालने के बाद कुछ राशि बचा पा रहे हैं.

> आंकड़े बताते हैं कि भारतीय उपभोक्ताओं की प्राथमिकताएं अब तात्कालिक खपत से हटकर घर, कारोबार, बच्चों की शिक्षा, कर्ज-मुक्ति और निवेश जैसी दीर्घकालिक जरूरतों की ओर बढ़ रही हैं .अपना घर खरीदने की बढ़ती इच्छा यह संकेत देती है कि वित्तीय आत्मविश्वास के साथ भारतीय परिवार संपत्ति निर्माण को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार मानने लगे हैं .

एनटीपीसी समेत तीन कंपनियों पर जुर्माना

नियमों के उल्लंघन पर एनएसई-बीएसई की कार्रवाई

कंपनियों ने जुर्माना माफ करने का किया अनुरोध

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनियों एनटीपीसी, आरईसी और एसजेवीएन पर शेयर बाजार के नियमों का अनुपालन नहीं करने के मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने कुल 59.14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

तीनों कंपनियों ने शेयर बाजार को दी गई अलग-अलग सूचनाओं में इसकी जानकारी दी है. एनटीपीसी के मुताबिक, सूचीबद्धता एवं प्रकटीकरण नियमों के नियम 17(1) के अनुपालन में कमी को लेकर बीएसई और एनएसई ने उस पर अलग-अलग 5,36,900 रुपये का जुर्माना लगाया है. यह राशि जीएसटी सहित है. कंपनी ने दोनों एक्सचेंजों को दिए जवाब में कहा कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और उसके निदेशक मंडल में निदेशकों की नियुक्ति अथवा उन्हें हटाने का अधिकार भारत सरकार के पास है. कंपनी ने कहा कि यह अधिकार विद्युत मंत्रालय के माध्यम से इस्तेमाल किया जाता है.

एनटीपीसी ने इसी आधार पर दोनों शेयर बाजारों से लगाए गए जुर्माने को वापस लेने का अनुरोध किया है.

35 हजार करोड़ निवेश, इथेनॉल संकट

चीनी 38 रुपये किलो से ऊपर हुई तो इथेनॉल उत्पादन मुश्किल

महाराष्ट्र में 35 हजार करोड़ का निवेश, 350 करोड़ लीटर सालाना

नवभारत न्यूज

मुंबई, 27 अगस्त देश का इथेनॉल उद्योग एक नए संकट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है. चीनी की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के कारण चीनी मिलों के लिए इथेनॉल उत्पादन आर्थिक रूप से नुकसान का सौदा बन सकता है.

उद्योग से जुड़े अनुमानों के मुताबिक, यदि चीनी का खरीद मूल्य 38 रुपये प्रति किलो से ऊपर रहता है तो मौजूदा इथेनॉल खरीद कीमतों पर उत्पादन करना मिलों के लिए लाभदायक नहीं रहेगा. अगले एक साल में चीनी के दाम 40 से 45 रुपये प्रति किलो के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है. ऐसी स्थिति में इस सीजन में बड़ी संख्या में चीनी मिलों के इथेनॉल संयंत्रों में उत्पादन ठप होने की आशंका है. इसका सीधा असर उस उद्योग पर पड़ेगा, जिसमें अकेले महाराष्ट्र की निजी और सहकारी चीनी मिलों ने करीब 35 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया है. पिछले पांच-छह वर्षों में सरकारी प्रोत्साहन और ब्याज सब्सिडी के कारण महाराष्ट्र में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता बढ़कर करीब 350 करोड़ लीटर सालाना हो गई है. अब महंगी चीनी और सीमित लाभ के कारण इस पूरी क्षमता के इस्तेमाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं

चीनी की कीमतों में संभावित तेजी के पीछे वैश्विक उत्पादन में कमी को प्रमुख कारण माना जा रहा है. अल नीनो के प्रभाव से भारत समेत दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया और प्रमुख चीनी उत्पादक देश ब्राजील में उत्पादन प्रभावित होने का अनुमान है. वैश्विक बाजार में फिलहाल चीनी की उपलब्धता को लेकर दबाव बना हुआ है और अगले सीजन में भी उत्पादन कम रहने की आशंका जताई जा रही है. इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ऊंची रह सकती हैं.

38 रुपये तक उत्पादन फायदेमंद

मौजूदा इथेनॉल खरीद कीमतों को देखते हुए चीनी मिलों के लिए कच्चे माल की लागत बेहद महत्वपूर्ण हो गई है . यदि चीनी का खरीद मूल्य करीब 35 से 39 रुपये प्रति किलो के बीच रहता है तो मिलों के लिए चीनी, शीरे या गन्ने के रस से इथेनॉल बनाना आर्थिक रूप से फायदेमंद रह सकता है . लेकिन कीमत 40 रुपये प्रति किलो से ऊपर जाने पर इथेनॉल उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी और मिलों के लिए इसे जारी रखना मुश्किल हो सकता है .

टाटा से 1.5 अरब डॉलर मांगे

एयर इंडिया को फंडिंग की जरूरत

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त टाटा को अब बड़ी फंडिंग की जरूरत पड़ रही है. टाटा समूह से एयर इंडिया के लिए 1.5 अरब डॉलर की नई फंडिंग मांगी गई है. यह रकम एयरलाइन की विस्तार योजनाओं और अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल की जाएगी.

एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह के पास आने के बाद यह अब तक की सबसे बड़ी फंडिंग होगी. एयरलाइन ने करीब 2.3 अरब डॉलर के संयुक्त घाटे के बीच यह फंडिंग जुटाने की तैयारी की है.

अधिग्रहण के बाद सबसे बड़ी फंडिंग- टाटा समूह ने वर्ष 2022 में एयर इंडिया समूह को अपने हाथ में लिया था. इसके बाद एयरलाइन के बेड़े के विस्तार और परिचालन में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश की योजना बनाई गई. इसमें पुराने विमानों को रिफिटिंग, नए विमान शामिल करना और नई परिचालन सुविधाएं विकसित करना शामिल है. कंपनी की विस्तार योजना के लिए लगातार पूंजी की जरूरत पड़ रही है. ऐसे में टाटा समूह से मांगी गई 1.5 अरब डॉलर की रकम एयर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है. एयर इंडिया को तत्काल जरूरत के अनुसार फंडिंग की जरूरत है.

शेयर बाजारों में गिरावट, सेंसेक्स 539 अंक टूटा

नवभारत न्यूज

मुंबई, 27 अगस्त भारतीय शेयर बाजारों में गुरुवार को बिकवाली का दबाव देखने को मिला और दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स 539.35 अंक यानी करीब 0.70 फीसदी लुढ़ककर 76,933.59 अंक पर बंद हुआ. वहीं, एनएसई का निफ्टी-50 सूचकांक 116.90 अंक की गिरावट के साथ 24,090.85 अंक पर आ गया. बाजार में प्रमुख शेयरों में बिकवाली के चलते निवेशकों की धारणा कमजोर रही.

6जी की वैश्विक दौड़ में भारत बढ़ाएगा कदम

- **6जी और क्वांटम तकनीक पर भारत का फोकस**
- **वैश्विक मानक तय करने में भागीदारी का लक्ष्य**

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली,27 अगस्त भारत दूरसंचार और अत्याधुनिक तकनीक के क्षेत्र में अब केवल नई तकनीकों को अपनाने वाला देश नहीं, बल्कि उनके विकास और वैश्विक मानक तय करने में योगदान देने वाला देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

केंद्रीय संचार राज्य मंत्री चंद्र शेखर पेम्मासानी ने कहा है कि 6जी, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में भारत के पास दुनिया के सामने अपनी तकनीकी क्षमता की छाप छोड़ने का बड़ा अवसर है. उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का लक्ष्य केवल 6जी तकनीक पर रिसर्च करना नहीं है, बल्कि इसके विकास में सक्रिय भूमिका निभाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी मानकों को तय करने की प्रक्रिया में प्रभावी भागीदारी करना भी है.

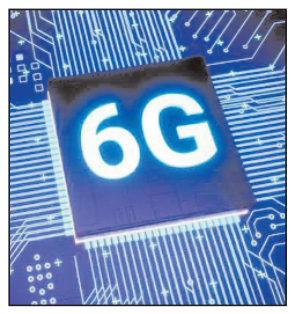

पेम्मासानी ने यह बात दूरसंचार विभाग के तहत काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के टेलीकॉम रिसर्च एवं डेवलपमेंट संगठन सी-डॉट के 43वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही.मंत्री ने कहा कि किसी भी नई तकनीक को सफल बनाने के लिए केवल शोध और विकास पर्याप्त नहीं है.

> 4जी और 5जी के क्षेत्र में मिली उपलब्धियों के बाद भारत को अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के विकास में भी अपनी भूमिका बढ़ानी होगी . इसके लिए मजबूत अनुसंधान तंत्र, उद्योग और अकादमिक संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल तथा स्वदेशी तकनीकी क्षमता जरूरी है . क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में शुरुआती बढ़त हासिल करने से भारत को वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में मजबूत स्थिति मिल सकती है .

कनाडाई निवेशकों को भारत में निवेश का न्योता

मंत्री सीतारमण ने कहा- युवा आबादी, बढ़ती खपत, डिजिटल ढांचा देश की बड़ी ताकत

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा की संस्थाओं और निवेशकों से भारत में निवेश बढ़ाने का आह्वान किया है.

टोरंटो में भारतीय कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. देश में युवा आबादी, बढ़ती खपत, निरंतर आर्थिक वृद्धि और तेजी से विकसित हो रहे पूंजी बाजार का ऐसा अनूठा संयोजन मौजूद है, जो दीर्घकालिक नजरिया रखने वाले निवेशकों के लिए बड़े अवसर पैदा करता है.

> सीतारमण ने कहा कि भारत और कनाडा के बीच वित्तीय क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं . कनाडा के बैंक, वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां और नियामक भारत के साथ मिलकर अगली पीढ़ी के डिजिटल वित्तीय बुनियादी ढांचे को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं . उन्होंने निवेशकों से भारत की दीर्घकालिक विकास क्षमता को देखते हुए यहां मौजूद अवसरों का लाभ उठाने की अपील की .

सीतारमण ने कहा कि भारत में हो रहा आर्थिक बदलाव केवल अस्थायी नहीं, बल्कि संरचनात्मक है. तेजी से बढ़ते शहरीकरण, मध्यम वर्ग के विस्तार और विश्वस्तरीय डिजिटल बुनियादी ढांचे के कारण अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में निवेश के नए रास्ते खुल रहे हैं.

हर महीने 2,000 रुपये बचाएं

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त हर महीने सिर्फ 2,000 रुपये की बचत भी लंबे समय में अच्छी रकम तैयार कर सकती है. लेकिन सवाल यह है कि इस रकम को कहां निवेश किया जाए—बैंक की एफडी, आरडी या फिर म्यूचुअल फंड की एसआईपी? तीनों विकल्पों में निवेश का तरीका, जोखिम और संभावित रिटर्न अलग-अलग होता है.

दिए गए अनुमान के मुताबिक, अगर 10 साल तक हर महीने 2,000 रुपये निवेश किए जाएं और एसआईपी में औसतन 12 फीसदी सालाना रिटर्न मिले, तो कुल रकम करीब 4.48 लाख रुपये हो सकती है. वहीं, 6.5 फीसदी की दर से आरडी में 10 साल बाद करीब 3.38 लाख रुपये मिल सकते हैं

अगर हर महीने 2,000 रुपये की एसआईपी 10 साल तक जारी रखी जाए, तो कुल निवेश 2.40 लाख रुपये होगा. 12 फीसदी औसत सालाना रिटर्न मानने पर करीब 2.08 लाख रुपये का अनुमानित लाभ हो सकता है. इस तरह कुल रकम लगभग 4.48 लाख रुपये हो सकती है. हालांकि, एसआईपी का रिटर्न बाजार पर निर्भर करता है और 12 फीसदी रिटर्न की गारंटी नहीं होती.

एआई के दौर में घटेंगी शुरुआती नौकरियां

- **साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ेगा**
- **रोबोटिक्स से बदलेंगे कई पारंपरिक काम**

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 27 अगस्त माइक्रोसॉफ्ट के सह-संस्थापक बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते प्रभाव को लेकर चेतावनी दी है. उनका कहना है कि एआई आने वाले वर्षों में कामकाज, रोजगार और साइबर सुरक्षा की तस्वीर तेजी से बदल सकता है.

दुनिया अभी इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है. गेट्स के मुताबिक, एआई का सबसे बड़ा असर करियर की शुरुआत करने वाले युवाओं पर पड़ सकता है, क्योंकि कंपनियां कई शुरुआती स्तर के काम मशीनों और एआई प्रणालियों से कराने लगेंगी

गेट्स ने अपने ब्लॉग में कहा कि एआई पिछली कई तकनीकी क्रांतियों की तुलना में कहीं तेजी से

युवाओं के करियर पर असर

बिल गेट्स के अनुसार, एआई से सबसे अधिक चुनौती उन युवाओं को मिल सकती है, जो नौकरी की शुरुआत करने वाले हैं . कंपनियां डेटा प्रोसेसिंग, ग्राहक सहायता, सॉफ्टवेयर से जुड़े कई काम और अन्य शुरुआती स्तर के कार्य एआई से कराने में सक्षम हो सकती हैं . इससे नए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अवसर घट सकते हैं .

समाचार विशेष

अब कितने अलग दिख रहे अखिलेश

लखनऊ, 27 अगस्त. उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जोर शोर से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे दिख रहे हैं. यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 2022 के चुनाव 2027 में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कितनी अलग दिख रही है.

सपा 2022 में जहां मूलरूप से मुस्लिम और यादव के अपने पारंपरिक पैटर्न पर टिकी थी, वहीं 2027 में अखिलेश यादव अपनी पार्टी के फलक को विस्तार देते दिख रहे हैं. 2022 में सपा जहां डर-डर कर कदम बढ़ा रही थी, वहीं 2027 में कार्यकर्ताओं के पास 2024 में मिली बड़ी जीत का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है. सपा 2027 में तमाम नये प्रयोग करती दिख रही है. वह कितना सफल होगा यह तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक बात तो है इसपर अखिलेश यादव रिस्क लेने में कंजूसी नहीं कर रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक अलग ही हलचल देखने को मिल रही है. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब सिर्फ चुनावी वादे नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पार्टी की पूरी पहचान और ब्रांड को बदलने में जुट गए हैं. अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत का जोश है, तो आप गलत हैं. यह सिर्फ भाषण देने का तरीका नहीं, बल्कि यूपी में सत्ता पाने के लिए बुना गया एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मास्टरप्लान है. समाजवादी पार्टी और उनके अध्यक्ष अखिलेश यादव 2022 के मुकाबले 2027 में ज्यादा आत्मविश्वास में दिख रहे हैं.

पीडीए का नया फॉर्मूला

अखिलेश यादव की राजनीति का सबसे दिलचस्प हिस्सा उनका नया पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है . पहले सपा को सिर्फ 'एमवाय' (मुस्लिम-यादव) समीकरण के चश्मे से देखा जाता था . अखिलेश ने इसे बदलने के लिए पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दिया . लेकिन अब अखिलेश ने इसमें एक नया मोड़ ला दिया है . लखनऊ में समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित 'प्रबुद्ध सम्मेलन' में अखिलेश ने खुले मंच से कहा- 'पीडीए में 'पी' का मतलब सिर्फ पिछड़ा नहीं, बल्कि 'पंडित' और 'पीड़ित' भी है .'

बाहुबली के गढ़ में बीएसपी ने चंद को बनाया प्रत्याशी

अस्मिता चंद ससुर के खिलाफ लड़ चुकी हैं चुनाव

गोरखपुर, 27 अगस्त. बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) आगामी यूपी चुनाव में मजबूती से लड़ाई में उतरने का प्रयास कर रही है. इसी वजह से बीएसपी अभी से कई सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रही है.

बीएसपी सुप्रीमो मायावती का मानना है कि समय से उम्मीदवार घोषित किए जाने से प्रत्याशी का तैयारी का पर्याप्त मौका मिलता है. इसी कड़ी में बीएसपी ने गोरखपुर-बस्ती मंडल में चिल्लूपार विधानसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा की है. बीएसपी ने यहां से अस्मिता चंद को प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है.

अस्मिता चंद का राजनीतिक सफर बेहद इंट्रेस्टिंग रहा है. वह करीब 20 साल से सक्रिय राजनीति कर रही हैं. पिछले तीन चुनाव से वह सत्ताधारी बीजेपी से टिकट पाने का प्रयास करती रही हैं. कहा जाता है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी से आश्वासन मिलने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिला था. इसके बाद से अस्मिता ने अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी को छोड़कर पूरे परिवार (दो बेटे और एक बेटी) के साथ बीएसपी की सदस्यता ले चुकी हैं. बीएसपी ने भी उनपर भरोसा करते हुए चिल्लूपार सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाने की घोषणा की है. अस्मिता चंद का परिवार पहले से राजनीति में सक्रिय रहा है. चिल्लूपार में अस्मिता के ससुर राजनारायण चंद ब्लॉक प्रमुख रहे हैं. वहीं उनके ससुर के बड़े भाई मारकंडेय चंद यूपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं. इसके अलावा अस्मिता के जेठ रणविजय चंद जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन रहे हैं.

> **मारकंडेय चंद के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं**
>
> अस्मिता लंबे समय से राजनीतिक ताकत पाने के प्रयास में लगी रही हैं . 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में वह धुरियापार विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट चाहती थीं . लेकिन आखिरी वक्त में यह टिकट उनके ससुर मारकंडेय चंद को मिल गया था . इसके बाद अस्मिता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने ससुर के खिलाफ दावेदारी ठोक दी थीं . उस चुनाव में ससुर और बहू की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लाभ मिल गया था . सपा प्रत्याशी राजेंद्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह चुनाव जीत गए थे .

छोटे चुनाव में बड़े नेताओं की दावेदारी

जयपुर, 27 अगस्त. राजधानी जयपुर में नगर निगम चुनाव की सियासी बिसात बिछने के साथ ही भाजपा के भीतर मेयर की कुर्सी को लेकर दावेदारियां तेज हो गई हैं. इस बार चुनाव भले ही पार्षद का हो, लेकिन भाजपा में टिकट के लिए सामने आ रहे बड़े नामों ने साफ कर दिया है कि कई नेताओं की नजर वार्ड की जीत से आगे मेयर की कुर्सी

पूर्व जिलाध्यक्षों से लेकर पूर्व मेयर, पूर्व डिप्टी मेयर, संगठन के पदाधिकारियों और प्रभावशाली नेताओं तक ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है. भाजपा ने पार्षद टिकट के लिए निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन मांगे हैं. आवेदन जिला स्तर पर जमा हो रहे हैं. अब तक 150 वार्डों के लिए 2500 से अधिक सामने आए नामों और नेताओं की सक्रियता को राजनीतिक नजरिए से देखें तो जयपुर नगर निगम का यह चुनाव भाजपा के लिए केवल पार्षद चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि पार्टी के भीतर अगले मेयर के चेहरे की तलाश का चुनाव भी बनता दिखाई दे रहा है. भाजपा टिकट के लिए आवेदन करने वाले नेताओं में कई ऐसे चेहरे हैं, जिनका संगठन और जयपुर की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है. वैश्य समाज से पूर्व मेयर निर्मल नाहटा, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील कोठारी, पूर्व उपमहापौर पुनीत कर्णावट, पूर्व शहर जिलाध्यक्ष संजय जैन, आईटी संयोजक अजय विजयवर्गीय, जिला महामंत्री राजेश तांबी और मौजूदा जयपुर चुनाव प्रभारी विमल अग्रवाल जैसे नाम चर्चा में हैं. इन नेताओं की दावेदारी को सिर्फ पार्षद बनने की सामान्य इ' छा के तौर पर नहीं देखा जा रहा.

राजनीतिक हलकों में माना जा रहा है कि इनमें से कई नेता ऐसे हैं, जिनकी नजर निगम की शीर्ष कुर्सी पर है.

आवेदन नहीं करने वाले भी रेस में

दिलचस्प बात यह है कि मेयर की दौड़ केवल आवेदन करने वाले नेताओं तक सीमित नहीं है . भाजपा में कुछ ऐसे बड़े चेहरे भी हैं, जिन्होंने अभी पार्षद टिकट के लिए औपचारिक आवेदन नहीं किया है, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं . पूर्व मेयर और पूर्व विधायक अशोक लाहोटी का नाम इसी कड़ी में देखा जा रहा है . उनके अलावा जयपुर शहर भाजपा के मौजूदा जिलाध्यक्ष अमित गोयल को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं हैं .

विशेष

चिराग की पार्टी यूपी में चुनाव लड़ेगी

नई दिल्ली, 27 अगस्त. भाजपा की सहयोगी पार्टियों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी दो ही ऐसी पार्टियां है, जो गठबंधन में दो से 'यादा रा'यों में भाजपा के साथ सीटों की साझेदारी करती हैं. भले सीटों की संख्या प्रतीकात्मक है लेकिन यह बड़ी बात है.

भाजपा ने जदयू और लोजपा दोनों को झारखंड में एक एक सीट दी थी और दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टियों को एक एक सीट दी गई थी. झारखंड में जदयू और लोजपा दोनों के एक एक विधायक जीते हैं. दिल्ली में दोनों चुनाव हार गए. अब उत्तर प्रदेश में चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. एक समय जदयू भी यूपी में लड़ने की तैयारी करती थी. पिछले चुनाव में तो नीतीश कुमार के ही वहां से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही थी. लेकिन अब जदयू ने बिहार से बाहर की राजनीति लगभग बंद कर दी है.

बहरहाल, जानकार सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं को उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारी करने को कहा है. ध्यान रहे यूपी में अगले साल फरवरी में चुनाव होना है और उससे पहले करीब 20 फीसदी दलित वोट की खींचतान शुरू हो गई है. मायावती की बसपा के साथ साथ चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी दलित वोट की बड़ी दावेदार है. दोनों नेता जाटव समाज